[Dr. Yelamanchili Sivaji]

dissolved. But the same yardstick has not been applied in Andhra Pradesh to restore law and order nor was there any warnning from the Union Government... *(Interruptions)*...

AN HONOURABLE MEMBER: Shame on the part of the ruling party

DR. YELAMANCHILI SIVAJI; Nobody is there.

AN HONOURABLE MEMBER: All vacant!.. . *(Interruptions),,* .

DR. YELAMANCHILI SIVAJI: During 1983 when there was a glut in tobacco market, firings took place and three tobacco growers were killed by the police firing at Tanguturu in the Prakasam District. Thereby the Andhra Pradesh Tobacco Growers Co-operative Society came into existence. That society helped the growers to give them relief whenever there was a glut.

Sir, due to the ad-hoc treatment by the Union Government as well as the slipshod attitude and quixotic attti-tude of the Union Government the production of the FCV tobacco in the country went down from 3 lakh metric tonnes to 75,000 metric tonnes this year. Even the 75,000 metric tonres has not been properly utilised or exported for the economic welfare of the country.

When all the traders collude together and try to control the market, the Government agencies like the STC are conspicuously absent at the auction platforms to see that the prices are stabilised. This year the cost of production of tobacco went up at least 100 per cent compared to that of the last year due to erratic weather conditions and high prices of fertilizers like' ammonium sulphate and others.

I would like to suggest that to stabilise and to safeguard the interests of the tobacco growers the State agencies like the STC may be pressed into action at the auction platforms. Tobacco yields about Rs. 200 crores of foreign exchange to the Union Government and more than Rs. 2,000 crores of excise duty to the exchequer. Unless the interests of the growers are safeguarded and protected, I am very much afraid that the country may have to pay a very high price by losing this excise tariff as well as the foreign exchange.

Demand for giving representation to Oriya Film Producers and Directors in the Eastern Zonal Film Censor Board

SHRIMATI MIRA DAS (Orissa): Sir, my special mention is on harassment of the film-producers in the Oriya language.

Sir, you know, Orissa is culturally very rich and also it has great scenic beauty. In spite of that Oriya producers are not getting much preference in producing pictures in Oriya because of their economic conditions. There was a time when other producers, film producers from outside used to dub the Telugu, the Bengali and the Tamil pictures in the Oriya language, and for everything, for production and for direction, the Oriya film-makers were depending on outsiders. But now we have our own studio. We are having indoor and outdoor shootings also. We have facilities of recording. We are now able to make 15 to 20 pictures in a year. But we do not have anybody in the Eastern Zonal Film Censor Board. Therefore, even if the Oriya picture-makers spend so much of money, hardly two to three pictures are being passed by the Censor Board, and the rest of the producers face very miserable economic conditions.

Sir, my request, submission, through you, is that in the Eastern Zonal Film Censor Board, Oriya film-producers

ana directors should be taken as Members, and they should be given sufficient opportunity to develop the Oriya pictures in future.

SHRI SARADA MOHANTY (Orissa): Sir, I associate myself.

Need to give matching grants by **the** Central Government to the States Minorities Financial Cooperations

श्री मोहम्मद खलीलुर रहमान :(आन्ध्र प्रदेश) : वाइस चेयरमैन साहब, हमारे मुल्क की चंद रियासतों में अकलियतों की फला-बहबूदी के लिए उनकी पसमांदगी को दूर करने के लिए वहां की रियासत हुकूमतों ने माइनोरिटीज़ फाइनेंशियल कारपोरेशंस कायम की हैं। चुनांचे आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश बिहार, गुजरात और कर्नाटक में इस किस्म के माइनोरिटीज फाइनेंसिल कारपोरेशंस बनाय गय हैं और वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने एक लिमिटेड ग्रांट उन फाइनेंस कारपोरेशंस को मंजूर की हुई है। हम देख रहे हैं कि जिन एम्स एंड आब्जक्ट्स के तहत माइनोरिटीज फाइननेशिल कारपोरेशंस बनाये गये हैं उसकी तकमील नहीं हो रही है। जो रियासती हुकूमतों की जानिब से उन्हें ग्रांट मंजूर की गई है वह इन्तहाई नाकाफी है। जो माइनोरिटीज फाइनेंसिल कारपोरेशन्स बनाई गई हैं, जाहिर है कि वे कोई खास अगराज़ो मकसद को सामने रखकर बनाई गई हैं लिहाज़ा उन अगराज़ों मकासिद की तकमील के लिए जरुरी हैं कि वहां की रियासती हुकूमतें उन्हें खातिरखा इमदाद दे। रियासत हुकूमतों के मसाइल क्योंकि महदूद होते हैं इसलिए उन महदूद मसाइलों को सामने रखते हुए वहां की हुकूमतों ने जो इमदाद दी है वह इन्तहाई नाकाफी है। लिहाजा जरुरत इस बात की है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट भी उतनी ही मैचिंग ग्रांट अपनी जानिब से कायम फाइनानशल माइनोरिटीज कारपोरेशन को दे ताकि रियासती हुकूमतों की ग्रांट और सेन्ट्रल गवर्नमेंट की जो मैचिंग ग्रांट होती है उससे खातिरखां जमा होगी और जाहिर है कि वहां जो माइनोरीटीज़ के नौजवान हैं उनकी मुआशी पसमांदगी और तालीमी पसमांदगी दूर हो सकेगी। लिहाजा मैं गवर्नमेंट आफ इंडिया से यह पुरजोर मुतालबा करता हूं कि जहां कहीं माइनोरिटीज फाइनानशल कारपोरेशन हैं वहां उन फाइनानशल कारपोरेशन्स को मैचिंग ग्रांट खातिरखांह मिकदार में दें। दूसरे हुकूमतें हिन्द से मतालबा है कि वह सेन्ट्रल लवल पर खुद इस किस्म का एक माइनोरिटी फीइनानशल कारपोरेशन्स बनाये और उसको काफी ग्रांट दे। यहां से भी माइनोरिटीज के जो नौजवान हैं उनकी माशी पसमांदगी और तालिमी पसमांदगी और उनके फला-बहबूद के लिए सेन्ट्रल गवर्नमेंट का माइनोरिटी फाइनेंस कारपोरेशन रहेगा तो उससे भी इमदाद मिलेगी। तीसरे मुतालबा यह है कि हम यह देख रहे हैं कि जो कुछ ग्रांट दी जा रही है वह जो फाइनेंससिस कारपोरेशन्स हैं 20 परसेंट मारीजनल मनी के तौर पर लोन देती हैं। बाकी 80 परसेंट बैंकर्स को देना पड़ता है। माइनोरिटीज फाइनेसिस कारपोरेशन्स ग्रांट 20 परसेंट मंजूर करने के बाद भी बैंकर्स उनके साथ प्रोपर्ली कोआपरेट नहीं कर रह हैं। माननीय यशवंत सिन्हा जी यहां नहीं हैं, मैं उनसे पुरजोर मुतालबा करना चाहता हूं कि बेंकर्स के वजीरे फाइनेंस, जितने हमारे नेशनलाइज्ड बैंकस के हैं उनको यह हिदायत दें कि जो कुछ माइनोरिटीज फाइनेंसिल कारपोरेशन्स हैं 20 परसेंट या मारीनजल अमाउंट मंजूर करती हैं बाकी 80 परसेंट भी ग्रांट वह इन्हीं इदारों को बैंकर्स दे और उनके साथ पूरा-पूरा ताबून करे।

†[شری محمد خلیل الرحمان (آندھرا پردیش) : وائس چیرمین صاحب - ہمارے ملک کی چند ریاستوں میں اقلیتوں کی فلا بہبودی کیلئے انکی پسماندگی کو دور کرنے کے لئے وہاں کی ریاست حکومتوں نے مائناریٹیز فائینینشیل کارپوریشنس

†Transliteration in Arabic Script